



Daily करेंट अफेयर्स

» 25 जून 2025

NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. त्रिपुरा में साक्षरता दर 95.6% तक पहुंच गई है और यह गोवा और मिजोरम के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।



त्रिपुरा ने ULLAS वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के तहत 95.6% साक्षरता दर हासिल की है, जिससे 23 जून 2025 को देश के तीसरे "पूर्ण साक्षर" राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है - जो बुनियादी साक्षरता से आगे बढ़कर कार्यात्मक कौशल को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- 23 जून 2025 को अगरतला के रवींद्र सतबर्षिकी भवन में CM माणिक साहा ने औपचारिक रूप से त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6% होने की घोषणा की। यह शिक्षा मंत्रालय और UNESCO द्वारा "पूर्ण साक्षर" दर्जे के लिए निर्धारित 95% की सीमा को पार कर गया है।

- ULLAS (Understanding Lifelong Learning for All in Society) कार्यक्रम ने केवल पढ़ना-लिखना नहीं, बल्कि कार्यात्मक साक्षरता जैसे डिजिटल ज्ञान, वित्तीय समझ, अंकगणित, और जीवन कौशल पर भी जोर दिया, विशेषकर 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए।

- त्रिपुरा की साक्षरता कहानी स्थिर प्रगति को दर्शाती है - 1961 में मात्र 20.24% से 2011 तक 87.22%, 2023-24 में 93.7% तक पहुंच गई, और अंततः 2024-25 में 95.6% तक बढ़ गई।

Key Points:-

(i) NEP-2020 के तहत शुरू की गई केंद्र प्रायोजित ULLAS योजना का लक्ष्य 2027 तक सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता हासिल करना है। त्रिपुरा में, इसने डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, बहुभाषी सामग्री (बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक) और एक मोबाइल ऐप-आधारित शिक्षण मंच को जोड़ा।

(ii) अभियान में 2,228 स्वयंसेवी शिक्षक तैनात किए गए, 943 सामाजिक जागरूकता केंद्र स्थापित किए गए और युवा साक्षरता कोर को संगठित किया गया। साक्षरता अभियान बाज़ारों, आंगनों और दूरदराज की पहाड़ियों तक भी फैला हुआ था।

(iii) यह उपलब्धि त्रिपुरा को गोवा और मिजोरम के साथ जोड़ती है, SDG 4 के तहत 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने के भारत के मिशन को बल देती है, और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

2. भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है और इसका लगभग 49% हिस्सा अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त हो रहा है।



जून 2025 में, भारत सरकार (GoI) ने अद्यतन डेटा जारी किया, जिसमें खुलासा हुआ कि भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 2015-16 में 305 गीगावाट से बढ़कर

476 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई है। उल्लेखनीय रूप से, इस क्षमता का लगभग 49% अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है, जो भारत की ऊर्जा प्रोफ़ाइल में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

- जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 476 गीगावाट है, जो 10 साल की अवधि में लगभग 56% की वृद्धि दर्शाती है। यह परिवर्तन भारत के ऊर्जा विविधीकरण, सतत विकास और कम कार्बन निर्भरता के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। बिजली क्षेत्र का नेतृत्व जीवाश्म और गैर-जीवाश्म दोनों स्रोतों द्वारा किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में तेज वृद्धि होती है।

- कुल स्थापित क्षमता में से 49% (235.7 गीगावाट) अब गैर-जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकियों से प्राप्त की जाती है, जिसमें 226.9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (RE) जैसे सौर, पवन, बायोमास और छोटे हाइड्रो और 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है। यह सरकार के 2030 स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक प्रमुख नीति और बुनियादी ढाँचा उपलब्धि है।

- इस बीच, थर्मल ऊर्जा प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है, जो कुल क्षमता का 50.52% (240 गीगावाट) है। इसमें से, कोयला आधारित संयंत्र अकेले थर्मल क्षमता का 91% से अधिक योगदान देते हैं, जो देश की चरम बिजली मांग को पूरा करने और बेस लोड उपलब्धता सुनिश्चित करने में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) भारत का बिजली उत्पादन उत्पादन भी काफी हद तक बढ़ा है, जो 2015-16 में 1,168 बिलियन यूनिट (BU) से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 1,824 BU हो गया है। यह सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) जैसी योजनाओं के तहत बढ़ी हुई औद्योगिक मांग और बेहतर घरेलू विद्युतीकरण दोनों को दर्शाता है।

(ii) देश में ऊर्जा की उपलब्धता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 45.8% की वृद्धि हुई है, जो 2013-14 में 957 किलोवाट-घंटे (kWh) से

बढ़कर 2023-24 में 1,395 kWh हो गई है। यह वृद्धि बेहतर बिजली विश्वसनीयता, 24x7 आपूर्ति लक्ष्य और ग्रामीण और अर्ध-शहरी बिजली पहुंच में वृद्धि को दर्शाती है।

(iii) स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग तीन गुनी हो गई है, जो मार्च 2014 में मात्र 76.37 गीगावाट थी, जो जून 2025 तक 226.9 गीगावाट हो गई है। अकेले सौर ऊर्जा क्षमता नाटकीय रूप से 2.8 गीगावाट से बढ़कर 110.9 गीगावाट हो गई है, और पवन ऊर्जा 51.3 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत अपने COP26 जलवायु लक्ष्यों के तहत प्रतिबद्ध 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता तक पहुंचने की राह पर है।

3. भारतीय रेलवे ने शून्य प्रीमियम लागत पर कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा शुरू किया।



जून 2025 में, भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक कल्याणकारी पहल शुरू की, जिसके तहत अपने कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम कटौती के, उनके वेतन पैकेज बैंक खातों के माध्यम से दुर्घटना मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।

- इस नई शुरू की गई योजना के तहत रेलवे कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को ₹1 करोड़ का मुआवज़ा दिया जाएगा, जिसमें वेतन से कोई बीमा प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। पात्रता के लिए केवल

एक भागीदार बैंक (जैसे, SBI) के साथ वेतन पैकेज खाता होना आवश्यक है।

- इस योजना का पहला दावा मुरादाबाद डिवीजन के लोको पायलट सुशील लाल के परिवार को दिया गया, जिनकी मार्च 2025 में दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने 21 जून को दिल्ली में ₹1 करोड़ का चेक सौंपा।

- दुर्घटना के बाद, भागीदार बैंक दावे की पुष्टि करता है और नामांकित व्यक्ति को सीधे ₹1 करोड़ का भुगतान करता है, भले ही दुर्घटना झूटी पर हुई हो या नहीं। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया गति और आसानी को रेखांकित करती है।

Key Points:-

(i) यह योजना देश भर के सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होती है। भारतीय रेलवे प्रमुख यूनियनों- ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (AIRF) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) के साथ मिलकर काम कर रहा है और नामांकन को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर और जागरूकता अभियान चला रहा है।

(ii) रेलवे कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यावसायिक खतरों को पहचानते हुए, यह पहल परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाती है। यह भारतीय रेलवे की अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(iii) यह ₹1 करोड़ की योजना मानक अनुग्रह भुगतान और मौजूदा बीमा कार्यक्रमों का पूरक है, जो कर्मचारियों के लिए अधिक व्यापक सुरक्षा जाल प्रदान करती है और व्यापक कल्याण कवरेज सुनिश्चित करती है।

4. अडानी ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया।



23 जून 2025 को, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला 5 मेगावाट (MW) ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया। यह सुविधा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित, ऑफ-ग्रिड है, और भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- भारत का पहला ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट अहमदाबाद स्थित अनिल (अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा बनाया गया है, जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है। यह परियोजना गुजरात के कच्छ में स्थित है, और पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है - एक एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ मुख्य ग्रिड से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है।

- यह संयंत्र इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक का उपयोग करता है, जो बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, जिसे औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह भारी उद्योगों में ग्रे हाइड्रोजन और जीवाश्म ईंधन को बदलने के भारत के प्रयास के अनुरूप है।

- इस सुविधा को जो अलग बनाता है वह है इसका पूरी तरह से स्वचालित, बंद-लूप इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम, जो

वास्तविक समय के सौर ऊर्जा इनपुट के लिए गतिशील रूप से अनुकूल होता है। यह संयंत्र को अत्यधिक कुशल, सुरक्षित और सौर ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव के प्रति लचीला बनाता है, जो हाइड्रोजन उत्पादन में एक तकनीकी नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है।

Key Points:-

(i) यह प्लांट प्रति रिफिल 25 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, जिससे हाइड्रोजन वाहनों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक ईंधन मिल सकता है। अवधारणा के प्रमाण (POC) के रूप में, यह एक बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए आधार तैयार करता है जिसे ANIL गुजरात के मुंद्रा में विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक पैमाने पर हाइड्रोजन और व्युत्पन्न उत्पादन करना है।

(ii) इस पायलट प्लांट से सालाना 350 मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, जो हर साल 13,000 पेड़ लगाने के बराबर है। यह 2023 में 2.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के बजट के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के उद्देश्यों का सीधे तौर पर समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता है।

(iii) मुंद्रा में अनिल के व्यापक हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल और संधारणीय विमानन ईंधन (SAF) का एकीकृत उत्पादन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, यह संयंत्र सौर मॉड्यूल, वेफर्स, पवन टरबाइन जनरेटर और इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करेगा, आयात को कम करेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन का समर्थन करेगा।

5. आपातकाल (25 जून 1975-77) के 50 साल पूरे होने पर देशभर में 'संविधान हत्या दिवस' मनाया गया।



25 जून 2025 को, भारत ने 1975-77 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाया, जो एक राष्ट्रीय पहल थी जिसमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के निलंबन पर प्रकाश डाला गया और संविधान की बहादुरी से रक्षा करने वालों को सम्मानित किया गया।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय (MHA) के तहत भारत सरकार ने जुलाई 2024 से 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में घोषित किया है। एक साल तक चलने वाले कार्यक्रम (जून 2024-जून 2026) में नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सेमिनार, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और शैक्षिक आउटरीच शामिल हैं।

- 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) के तहत "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। यह "आंतरिक अशांति" के आधार पर इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र आपातकाल था, जिसे बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया।

- 21 महीने के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई और विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं सहित लगभग 1.1 लाख लोगों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिया गया। जबरन सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम और सत्ता का केंद्रीकरण बड़े अत्याचार थे।

Key Points:-

(i) 25 जून 2025 को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने के लिए पूरे भारत में कई राज्य स्तरीय स्मरणोत्सव और समारोह आयोजित किए गए। चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने टैगोर थिएटर में एक भव्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जहाँ पत्रकारों, छात्रों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन आंदोलन की भूमिका को याद किया गया। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आपातकाल को "भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक कलंकित घटना" बताया, जबकि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रविकुमार त्रिपाठी ने उस अवधि के दौरान संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर एक व्याख्यान दिया। इस बीच, कुरुक्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) एस.पी. सिंह बघेल ने भारतीय संविधान की तुलना गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबिल जैसे पवित्र ग्रंथों से की, और इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक सुधार राष्ट्रीय हित में किए जाने चाहिए, न कि राजनीतिक सुविधा के लिए।

(ii) 25 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर उन "असंख्य व्यक्तियों" को सम्मानित किया, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था और इसके अत्याचारों को झेला था, तथा लोकतंत्र में उनके योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दी।

(iii) संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकारें (जैसे, ओडिशा) युवा दर्शकों के लिए प्रदर्शनियाँ, फिल्म स्क्रीनिंग, कार्यशालाएँ और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। ये कार्यक्रम नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और आपातकालीन युग से ऐतिहासिक सबक पर जोर देते हैं।

6. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'पासपोर्ट सेवा 2.0' का शुभारंभ किया और देश भर में ई-पासपोर्ट शुरू किया।



25 जून 2025 को, 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए, बायोमेट्रिक चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट के राष्ट्रव्यापी रोलआउट के साथ-साथ पासपोर्ट सेवा 2.0 का अनावरण किया।

- पासपोर्ट सेवा 2.0 पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) के तहत भारत के पासपोर्ट जारी करने वाले प्लेटफ़ॉर्म का उन्नत संस्करण है। यह AI-समर्थित सेवाओं, बेहतर डिजिटल एकीकरण और पासपोर्ट की बढ़ती मांग को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए सुरक्षित वर्कफ़्लो के साथ बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव पेश करता है।

- इस पहल ने आधिकारिक तौर पर चिप-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) जारी करना शुरू किया, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप्स से लैस हैं और पासपोर्ट धारक की तस्वीर और फिंगरप्रिंट सहित एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करते हैं। ई-पासपोर्ट का राष्ट्रव्यापी रोलआउट 25 जून 2025 को शुरू हुआ और अब यह भारत में सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSK) में पूरी तरह से चालू है।

- पासपोर्ट सेवा 2.0 पहल के हिस्से के रूप में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने EASE फ्रेमवर्क पेश किया, जिसका अर्थ है संवर्धित, AI-संचालित, सुचारू और संवर्धित सुरक्षा। इस ढांचे के तहत, सरकार का लक्ष्य डिजिटल सेवा वितरण (E) सुनिश्चित करना, पासपोर्ट संचालन में AI समर्थन को

एकीकृत करना (A), चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट (S) के माध्यम से निर्बाध विदेश यात्रा की सुविधा प्रदान करना और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत एन्क्रिप्टेड डेटा सुरक्षा उपायों को लागू करना (E) है।

Key Points:-

(i) नया PSP 2.0 भारत के डिजिटल इंडिया लक्ष्यों के अनुरूप है। मुख्य एकीकरण में mPassport सेवा ऐप, डिजिलॉकर कनेक्टिविटी, mPassport पुलिस ऐप और “कहीं से भी आवेदन करें” सुविधा शामिल है। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 2014 में 77 से बढ़कर आज 523 हो गई है।

(ii) नवीन रूप से लॉन्च किए गए ई-पासपोर्ट प्रवासन प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए आईसीएओ-समर्थित ई-गेट्स (International Civil Aviation Organization मानकों) के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इन पासपोर्टों में Basic Access Control (BAC) और Extended Access Control (EAC) जैसे उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकें शामिल हैं, जो डेटा की सुरक्षा और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करती हैं। यह प्रणाली पासपोर्ट धोखाधड़ी, जालसाजी और पहचान की चोरी जैसे मामलों को काफी हद तक कम करती है। विशेष रूप से, वर्तमान पारंपरिक पासपोर्ट उनकी निर्धारित समाप्ति तिथि तक वैध और उपयोग योग्य रहेंगे, जिससे सभी पासपोर्ट धारकों के लिए एक सहज परिवर्तन सुनिश्चित हो सकेगा।

(iii) जयशंकर ने पासपोर्ट अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय मिशन के कर्मचारियों के समर्पित काम की प्रशंसा की। उन्होंने सभी जारी करने वाले अधिकारियों से पासपोर्ट सेवाओं में गुणवत्ता, पहुंच, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया।

INTERNATIONAL

1. नैनो यूरिया लॉन्च करने के चार साल बाद IFFCO ब्राजील में भारत का पहला विदेशी नैनो-उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा।



जून 2025 में, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी (IFFCO) ने ब्राजील के पराना में अपनी पहली विदेशी नैनो-उर्वरक उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की - 2021 में भारत में अपने नैनो-यूरिया लॉन्च और अप्रैल 2023 में नैनो-DAP रोलआउट की सफलता का लाभ उठाते हुए।

● IFFCO अक्टूबर 2025 तक ब्राजील के पराना में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 12 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करते हुए नैनोवेंशन्स ब्रासिल के साथ साझेदारी करेगा। ब्राजील और अमेरिका दोनों में परीक्षण अनुमोदन प्राप्त करने के बाद यह सहकारी की विदेश में पहली नैनो-उर्वरक विनिर्माण इकाई है।

● जून 2021 में भारत का पहला नैनो-यूरिया और अप्रैल 2023 में लिक्विड नैनो-DAP लॉन्च करने के बाद से, इफको ने वित्त वर्ष 25 में ~26 मिलियन नैनो-यूरिया बोतलें बेची हैं। फील्ड ट्रायल में 5.7% उपज में वृद्धि देखी गई, और ब्राजील, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को शुरूआती नैनो-उर्वरक निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है।

● ब्राजील के प्लांट में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र शामिल होगा जिसका उद्देश्य स्थानीय मिट्टी और फसल की जरूरतों के अनुकूल फॉर्मूलेशन विकसित करना होगा। स्थानीय विश्वविद्यालयों और ब्राजील के टेक्नोलॉजिको पराना (Tecpar) जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग से प्रौद्योगिकी अनुकूलन में सहायता मिलेगी।

Key Points:-

(i) यह सुविधा शुरू में प्रति वर्ष 5 मिलियन लीटर नैनो-उर्वरक का उत्पादन करेगी, जिसकी योजना पाँच वर्षों के भीतर क्षमता को दोगुना करने की है। यह कॉम्पैक्ट प्रारूप रसद लागत, लैंडफिल अपशिष्ट को कम करने और फसल उपयोग में पोषक तत्व दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है।

(ii) 20-50 नैनोमीटर के बीच नैनोकण आकार वाले नैनो-उर्वरक, पारंपरिक यूरिया (30-50%) की तुलना में बेहतर अवशोषण (80% से अधिक अवशोषण) प्रदान करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की बर्बादी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और रासायनिक अपवाह में कमी आती है।

(iii) ब्राजील में स्थानीय नैनो-उर्वरक उत्पादन की स्थापना से वैश्विक स्तर पर "आत्मनिर्भर भारत" को मजबूती मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इससे इफको को नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित कृषि-इनपुट में वैश्विक नेता के रूप में स्थान मिलेगा, जिससे पारंपरिक उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी।

2. WEF की 2025 प्रौद्योगिकी अग्रदूतों की सूची में चयनित 10 स्टार्ट-अप्स में भारत का नाम शामिल, डीप-टेक नवाचार पर प्रकाश डाला गया।

23 जून, 2025 को जिनेवा, स्विटजरलैंड में मुख्यालय वाले विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने प्रतिष्ठित 'टेक्नोलॉजी पायनियर्स' कार्यक्रम के अपने 2025 के समूह का अनावरण किया। वैश्विक स्तर पर चुने गए 100 अत्याधुनिक स्टार्ट-अप में से 10 भारत से हैं, जो अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में डीप-टेक इनोवेशन में देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

● WEF द्वारा 2025 प्रौद्योगिकी अग्रदूतों के समूह में 28 देशों के 100 प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप शामिल हैं, जिन्हें विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की उनकी क्षमता के आधार पर चुना गया है। भारत द्वारा 10 स्टार्ट-अप का चयन विकासशील देशों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व में से एक है।

● चयनित 10 भारतीय स्टार्ट-अप स्पेस टेक, हेल्थटेक, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक से जुड़े हैं। विशेष रूप से, अग्रिकुल कॉसमॉस, गैलेक्सआई स्पेस और द ईप्लेन कंपनी - सभी IIT मद्रास में इनक्यूबेट किए गए हैं - एयरोस्पेस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनोवेशन में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

● वर्ष 2000 में शुरू किया गया, टेक्नोलॉजी पायनियर्स कार्यक्रम वैश्विक सामाजिक प्रभाव वाले सफल समाधान विकसित करने वाली शुरुआती चरण की कंपनियों का समर्थन करता है। WEF इन स्टार्ट-अप्स को प्रभाव-संचालित नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने विशेषज्ञ नेटवर्क, वैश्विक प्लेटफॉर्म और रणनीतिक सहयोग तक पहुँच प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम के तहत 1,200 से ज़्यादा स्टार्ट-अप को मान्यता दी गई है - जिसमें गूगल, Airbnb, पेपाल, ड्रॉपबॉक्स और स्पाटिफ़ाई जैसी दिग्गज कंपनियाँ शामिल हैं। इन कंपनियों ने डिजिटल वित्त, कंटेंट शेयरिंग और संचार जैसे क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव किया है।

(ii) 2025 के लिए थीम: चयनित फर्म WEF के 2025 फोकस क्षेत्रों को दर्शाती हैं: AI फॉर गुड, क्लाइमेट टेक, समावेशी फिनटेक, साइबर सुरक्षा, स्वच्छ गतिशीलता और स्वास्थ्य पहुंच। भारतीय समूह विशेष रूप से भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया के साथ संरेखित है।

(iii) WEF के मंच पर भारतीय स्टार्ट-अप को शामिल करने से तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर प्रकाश पड़ता है। IIT, IISc और BIRAC जैसे रणनीतिक इनक्यूबेटर्स द्वारा डीप-टेक रिसर्च को समर्थन देने के साथ, भारत चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रहा है।

3. सतत विकास रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड शीर्ष पर; भारत पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ।



जून 2025 में, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) ने अपनी 10वीं सतत विकास रिपोर्ट जारी की, जिसमें फिनलैंड को सर्वोच्च रैंक वाला देश बताया गया। पहली बार, भारत ने शीर्ष 100 में जगह बनाई - 66.95 अंकों के साथ 99वीं रैंक हासिल की।

- फिनलैंड 87.02 के स्कोर के साथ 2025 के लिए वैश्विक SDG सूचकांक में सबसे आगे है, उसके बाद स्वीडन (85.74) और डेनमार्क (85.26) का स्थान है। शीर्ष 20 देशों में से 19 यूरोपीय हैं, जो पारिस्थितिक चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के निरंतर प्रभुत्व को दर्शाता है।

- एक उल्लेखनीय सुधार के तहत, भारत 2024 में 109वें स्थान से उछलकर 2025 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में 99वें स्थान पर पहुंच गया। 66.95 के स्कोर के साथ यह पहली बार है जब भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है—यह उपलब्धि ऊर्जा पहुंच, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के कारण संभव हुई है।

- भारत के पड़ोसियों में, भूटान 74वें (70.5), नेपाल 85वें (68.6), मालदीव 53वें, श्रीलंका 93वें, बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान 140वें स्थान पर है, जो सतत विकास लक्ष्य प्रगति में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक

स्तर पर 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से केवल 17% ही वर्तमान में पटरी पर हैं। जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण, प्रेस स्वतंत्रता और मोटापे के खिलाफ लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र काफी पीछे हैं। हालाँकि, सबसे उल्लेखनीय प्रगति आवश्यक सेवाओं में देखी गई है, विशेष रूप से बिजली की सार्वभौमिक पहुंच (SDG 7), बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (SDG 3), और डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे (SDG 9) में।

(ii) 2015 से पूर्वी और दक्षिण एशिया वैश्विक SDG सुधारों में सबसे आगे हैं, जिसमें नेपाल (+11.1 अंक), कंबोडिया (+10), फिलीपींस (+8.6), बांग्लादेश (+8.3) और मंगोलिया (+7.7) ने महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया है। यह निरंतर सामाजिक-आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।

(iii) सेविले में विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4) (30 जून-3 जुलाई 2025) से पहले, रिपोर्ट में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी पुनर्निर्देशित करने के लिए वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार का आग्रह किया गया है, जिससे SDG लक्ष्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता बढ़ सके।

BANKING & FINANCE

1. अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI 7-दिवसीय रिवर्स रेपो के माध्यम से बैंकों से ₹1 ट्रिलियन निकालेगा।



27 जून 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम से ₹1 ट्रिलियन को अवशोषित करने के लिए 7-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य सिस्टम में अतिरिक्त धन को कम करना और अल्पकालिक ब्याज दरों को RBI की नीति दर के साथ संरेखित करना है।

● बैंकों के पास इस समय बहुत ज़्यादा अतिरिक्त पैसा है, जो ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है। RBI इस रिवर्स रेपो नीलामी का उपयोग बैंकिंग प्रणाली से अस्थायी रूप से ₹1 ट्रिलियन वापस लेने और अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए कर रहा है।

● रिवर्स रेपो में, RBI कुछ दिनों के लिए बैंकों से पैसे उधार लेता है और उन्हें ब्याज देता है। इससे RBI को अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को नियंत्रित करने और ब्याज दरों को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

● घोषणा के बाद ओवरनाइट लेंडिंग रेट (कॉल रेट) बढ़कर 5.30% हो गई, और शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी बिल की दरें भी बढ़ गईं। इससे बाजार की ब्याज दरों को RBI की मुख्य नीति दर के करीब लाने में मदद मिलती है।

Key Points:-

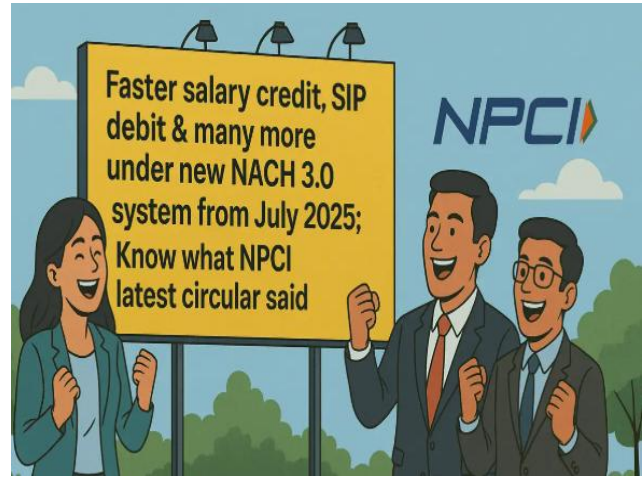
हाल ही में, RBI ने भी रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की और तरलता के स्तर को प्रबंधित करते हुए विकास को समर्थन देने के लिए CRR (नकद आरक्षित अनुपात) में कटौती की घोषणा की। यह रिवर्स रेपो कदम उन कदमों का पूरक है।

(ii) बैंक अब अतिरिक्त पैसे को RBI के पास सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं और ब्याज कमा सकते हैं। इससे जोखिम भरे ऋण देने से बचने में मदद मिलती है और बैंकिंग प्रणाली स्वस्थ और अधिक नियंत्रित रहती है।

(iii) RBI ने कहा कि वह जरूरत पड़ने पर इस तरह की अल्पकालिक नीलामी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब तक पूंजी प्रवाह पर दबाव नहीं होगा, तब तक वह दीर्घकालिक बॉन्ड बिक्री (OMO) नहीं करेगा। इससे RBI को तरलता को

समझदारी से प्रबंधित करने की सुविधा मिलती है।

2. NPCI ने बेहतर सुरक्षा के साथ तेजी से वेतन, EMIs और SIPs के लिए राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (NACH) 3.0 लॉन्च किया।



23 जून 2025 को, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने NACH 3.0 के लॉन्च की घोषणा की - जो इसके ब्लॉक पेमेंट प्लेटफॉर्म का उन्नत संस्करण है। इससे पूरे भारत में वेतन, पेंशन, EMI, SIP, स्कूल फीस और सब्सक्रिप्शन जैसे आवर्ती भुगतानों की गति, विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी।

● NACH NPCI द्वारा एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो वेतन, पेंशन, समान मासिक किस्तों (EMIs) और व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIPs) जैसे उच्च-मात्रा वाले आवर्ती भुगतानों को संभालती है। NACH 3.0 इसका उन्नत संस्करण है जिसे देरी को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर पीक ऑवर्स के दौरान।

● NPCI भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा स्थापित एक छत्र संगठन है जो UPI, IMPS, रुपये और NACH जैसी खुदरा भुगतान प्रणालियों को संचालित करता है। यह भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

● उन्नत प्रणाली में आसान उपयोग के लिए आधुनिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI), भुगतान फ़ाइलों को ट्रैक करने के लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड और जनादेश

अस्वीकृति के लिए तत्काल सूचनाएँ शामिल हैं। बैंक बिना किसी मैन्युअल निर्भरता के पासवर्ड रीसेट और शिकायतों का प्रबंधन कर सकते हैं।

Key Points:-

- (i) NACH 3.0 में प्रीटी गुड प्राइवैसी (PGP) एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल शामिल है। यह प्लेन-टेक्स्ट डाउनलोड को भी ब्लॉक करता है और सभी यूजर एक्टिविटी को लॉग करता है, जिससे डेटा प्राइवैसी और धोखाधड़ी की रोकथाम में काफी सुधार होता है।
- (ii) बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) अब आवर्ती भुगतानों को अधिक कुशलता से संसाधित कर सकती हैं, जिसमें कम त्रुटियाँ, तेज़ समाधान और विवाद समाधान के लिए स्व-प्रबंधित उपकरण शामिल हैं। EMI/SIP संग्रह में देरी भी कम हो गई है।
- (iii) उपभोक्ताओं को वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान, तथा बिना किसी दंड शुल्क के EMI और SIP का स्वतः डेबिट होने का लाभ मिलेगा। इससे बेहतर पारदर्शिता, कम विफलताएं और वित्तीय डेटा की मजबूत सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

ECONOMY & BUSINESS

1. L&T ने SEBI के नए ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के तहत ₹500 करोड़ मूल्य का भारत का पहला ESG बॉन्ड लॉन्च किया।



23 जून 2025 को, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। यह ₹500 करोड़ की पेशकश SEBI के नए ESG और स्थिरता-लिंकड बॉन्ड ढांचे के तहत जारी की गई है और भारत की ग्रीन फाइनेंस यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

● मुंबई स्थित इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर समूह L&T ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर भारत का पहला ईएसजी-अनुपालन बॉन्ड सूचीबद्ध करके इतिहास रच दिया है। बॉन्ड को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) के रूप में संरचित किया गया है, जो 6.35% की निश्चित वार्षिक कूपन दर के साथ ₹500 करोड़ जुटाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास की दिशा में पूंजी को आकर्षित करना है।

● ये बांड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के नए पेश किए गए ESG और स्थिरता-लिंकड बॉन्ड ढांचे के तहत जारी किए जाने वाले पहले बांड हैं, जो 5 जून 2025 को लागू हुए। यह ढांचा भारत के जलवायु और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए ESG-संबंधित वित्तीय साधनों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

● NCDs की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष है, जिसका अंतिम मोचन 19 जून 2028 को होगा। निवेशकों को वार्षिक ब्याज भुगतान मिलेगा। जारी करने की संरचना पारदर्शिता और निवेशक विश्वास सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से ESG-जागरूक संस्थागत खरीदारों के लिए।

Key Points:-

- (i) संपूर्ण लेन-देन हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) द्वारा एकमात्र प्रमुख संयोजक के रूप में किया गया। ESG वित्त में HSBC की वैश्विक विशेषज्ञता ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया और भारत के स्थायी वित्त पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशी रुचि को आकर्षित किया।
- (ii) L&T ने बॉन्ड को सेबी के दिशा-निर्देशों के तहत मापने योग्य ईएसजी प्रदर्शन लक्ष्यों से जोड़ा है। इनमें मीठे पानी की निकासी की तीव्रता में कमी और ग्रीनहाउस गैस (GHG)

उत्सर्जन में कटौती शामिल है। स्थिरता से जुड़े ये लक्ष्य L&T के 2035 तक जल तटस्थ और 2040 तक कार्बन तटस्थ बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

(iii) SEBI के स्थिरता-लिंक्ड बॉन्ड ढांचे के अनुसार, L&T को स्थिरता उद्देश्यों, द्वितीय-पक्ष की राय (SPOs) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) सहित विस्तृत खुलासे प्रकाशित करने होंगे। कंपनी जारी करने के बाद प्रभाव रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी, जिससे यह एक पारदर्शी और बेंचमार्क-सेटिंग ग्रीन फाइनेंस पहल बन जाएगी।

2. S&P ने वित्त वर्ष 26 में भारत के लिए 6.5% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है और भू-राजनीतिक जोखिमों की चेतावनी दी है।



24 जून, 2025 को, S&P ग्लोबल रेटिंग्स (USA) ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि पूर्वानुमान को 6.3% के अपने पहले के अनुमान से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। यह संशोधन “आर्थिक दृष्टिकोण एशिया-प्रशांत Q3 2025: लचीलापन भिन्न हो सकता है” शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर आशावाद को दर्शाता है।

● S&P ग्लोबल रेटिंग्स (जिसे पहले स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के नाम से जाना जाता था) ने वित्त वर्ष 2026 (2025-26) में भारत की GDP में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है,

जिसमें कम तेल की कीमतों, सहायक मौद्रिक नीति और अनुकूल कराधान उपायों जैसे मजबूत घरेलू कारकों का हवाला दिया गया है। यह संशोधन RBI के 6.5% के अपने पूर्वानुमान के अनुरूप है।

● वित्त वर्ष 26 के साथ-साथ, S&P ने भारत के वित्त वर्ष 27 के GDP विकास अनुमान को भी 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया, जो निरंतर आर्थिक गति को दर्शाता है। एजेंसी का मानना है कि संरचनात्मक सुधार, घरेलू खपत और भारत की ओर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव प्रमुख चालक हैं।

● सकारात्मक दृष्टिकोण कच्चे तेल की कम कीमतों, मौद्रिक सहजता (ब्याज दरों में कटौती), आयकर में छूट और सामान्य मानसून से प्रेरित है, जो सामूहिक रूप से उच्च ग्रामीण मांग, बेहतर मुद्रास्फीति नियंत्रण और पूंजी प्रवाह स्थिरता का समर्थन करते हैं।

Key Points:-

(i) S&P ने मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और ईरान-USA संघर्ष जैसे प्रमुख जोखिमों को चिन्हित किया है, जो वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल ला सकते हैं। भारत अपने कच्चे तेल का 90% और प्राकृतिक गैस का 50% आयात करता है, इसलिए यह बाहरी मूल्य झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।

(ii) S&P को उम्मीद है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 2025 में औसतन 4% रहेगी, जबकि 2024 में यह 4.6% होगी। इसके अतिरिक्त, वैश्विक मुद्रा दबावों के बीच, भारतीय रुपया (INR) दिसंबर 2025 तक 87.5 प्रति डॉलर तक गिर जाने का अनुमान है, जो दिसंबर 2024 में 86.6 से कम है।

(iii) बढ़ते तनाव के बावजूद, S&P ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अच्छी आपूर्ति है। इसने तेल की कीमतों में दीर्घकालिक व्यवधान की आशंका नहीं जताई है, जो भारत जैसी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिर आयात बिल और चालू खाता प्रबंधन का समर्थन करता है।

SPORTS**1. अर्जुन पुरस्कार विजेता ललित उपाध्याय ने ओलंपिक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया।**

23 जून 2025 को, अनुभवी भारतीय हॉकी फॉरवर्ड और अर्जुन पुरस्कार विजेता ललित कुमार उपाध्याय (31) ने ओलंपिक दिवस के साथ ही अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की - जो विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दशक लंबे उल्लेखनीय करियर का अंत था।

● ललित उपाध्याय ने 183 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया, 67 गोल किए और टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तीन हॉकी विश्व कप और कई बड़े टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया।

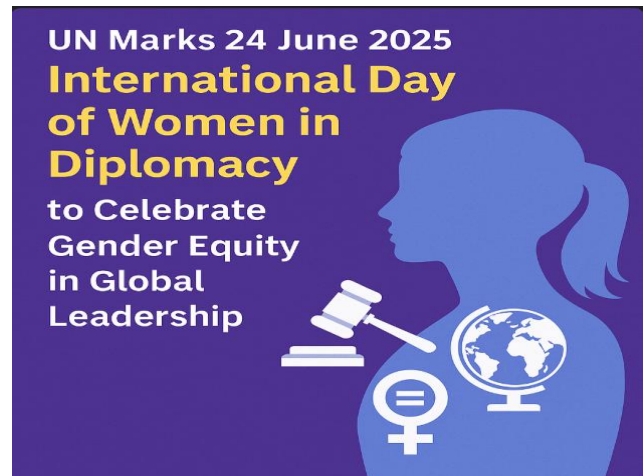
Key Points:-

(i) 2021 में, उन्हें हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार मिला। उन्होंने कई एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया - दो स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता - और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता।

(ii) उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भगतपुर गांव से आने वाले ललित की साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक पोडियम तक की यात्रा की हर तरफ तारीफ हो रही है। वह महान खिलाड़ियों के नक्शेकदम पर चलते हुए तीन विश्व कप में खेलने वाले यूपी के दूसरे खिलाड़ी बन गए। वह यूपी में

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर भी कार्यरत हैं।

(iii) ओलंपिक दिवस पर भारत के FIH प्रो लीग मैच के बाद घोषित अपने अंतरराष्ट्रीय संन्यास के बाद, ललित की योजना वाराणसी में जमीनी स्तर पर हॉकी को मजबूत करने, युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और यूपी पुलिस टीम के लिए घरेलू स्तर पर खेलना जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने की है।

IMPORTANT DAYS**1. संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक नेतृत्व में लैंगिक समानता का जश्न मनाने के लिए 24 जून 2025 को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।**

24 जून 2025 को, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने कूटनीति में महिलाओं का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDWID) मनाया, जिसमें समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देने, विदेशी मामलों में महिलाओं की समान भागीदारी और लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह दिन विश्व स्तर पर महिला राजनयिकों के योगदान का स्मरण करता है और अंतर्राष्ट्रीय शासन में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

● 2025 का विषय, "कूटनीति में महिला नेतृत्व के लिए संरचनात्मक बाधाओं को समाप्त करना", वैश्विक नीति, वार्ता, शांति स्थापना और उच्च स्तरीय राजनयिक

नियुक्तियों में महिलाओं के सामने आने वाली लगातार असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

- विषय संस्थागत सुधारों, लक्षित नीतिगत परिवर्तनों और सरकारी प्रणालियों के भीतर सांस्कृतिक बदलावों की वकालत करता है जो महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेतृत्व करने में सक्षम बनाते हैं।

- कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव A/RES/76/269 के माध्यम से मान्यता दी गई, जिसे 20 जून 2022 को 76वें सत्र के दौरान पारित किया गया। पहला वैश्विक आयोजन 24 जून 2023 को हुआ, और 2025 का उत्सव इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस का तीसरा संस्करण है। इस प्रस्ताव का समर्थन मालदीव ने किया और 190 से अधिक सदस्य देशों ने इसे सह-प्रायोजित किया।

Key Points:-

(i) इस दिन को मनाने के लिए, अंतर-संसदीय संघ (IPU) और UN Women ने संयुक्त रूप से 2025 "राजनीति में महिलाएँ" मानचित्र जारी किया, जो राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक प्रतिनिधित्व पर नज़र रखने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है। रिपोर्ट के अनुसार, निकारागुआ अपनी राष्ट्रीय संसद में 64.3% महिलाओं के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है, जबकि भारत केवल 5.6% महिला प्रतिनिधित्व के साथ 174वें स्थान पर है, जो एक प्रमुख कूटनीतिक और नीतिगत अंतर को उजागर करता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र ने दोहराया कि कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से संघर्ष समाधान अधिक प्रभावी होगा, शांति समझौते लंबे समय तक चलेंगे और वैश्विक स्तर पर विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व होगा। फिर भी, राजदूतों, विदेश सचिवों और शांति दूतों जैसी भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जो वैश्विक स्तर पर वरिष्ठ राजनयिक पदों के 25% से भी कम हैं।

(iii) भारतीय संदर्भ में, निरुपमा राव और रुचिरा कंबोज जैसी कई उल्लेखनीय महिला राजनयिकों के उभरने के बावजूद,

विदेशी सेवाओं में कुल मिलाकर लैंगिक समानता कम बनी हुई है। 2025 के IDWID समारोह में भारत और अन्य जगहों पर मजबूत सुधारों का आह्वान किया गया, जिसमें लैंगिक कोटा लागू करना, महिला राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण और सलाह का विस्तार करना और उच्च-दांव वाली बहुपक्षीय वार्ताओं में महिलाओं को शामिल करने को प्राथमिकता देना शामिल है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. डांगेटी जाह्नवी टाइटन्स अंतरिक्ष कक्षीय मिशन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार बनीं।



23 जून 2025 को, आंध्र प्रदेश के पलाकोल्लू की 23 वर्षीय डांगेटी जाह्नवी को 2029 में लॉन्च होने वाले ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए टाइटन्स स्पेस ऑर्बिटल मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार (ASCAN) के रूप में चुना गया। उनका चयन वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

- डांगेटी जाह्नवी पहली भारतीय हैं जिन्हें टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज (अमेरिका स्थित अंतरिक्ष उद्यम) द्वारा निजी क्षेत्र की कक्षीय उड़ान के लिए चुना गया है। उन्हें उद्घाटन ASCAN 2025 कोहोर्ट के हिस्से के रूप में चुना गया था।

- पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक जाह्नवी को नासा के

अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम (IASP) को पूरा करने वाली पहली भारतीय होने का गौरव भी प्राप्त है।

• टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन 2029 के लिए निर्धारित 5 घंटे की कक्षीय उड़ान है। इसमें दो पूर्ण पृथ्वी परिक्रमाएं, तीन घंटे तक निरंतर शून्य गुरुत्वाकर्षण शामिल है, और यह ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन तक यात्रा करेगा।

Key Points:-

(i) 2026 से शुरू होकर, जाह्नवी को NASA के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री कर्नल विलियम मैकआर्थर जूनियर के मार्गदर्शन में तीन साल का कठोर ASCAN प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा - जिसमें उड़ान सिमुलेशन, अंतरिक्ष यान प्रणाली, उत्तरजीविता प्रशिक्षण, चिकित्सा मूल्यांकन और खगोल विज्ञान अनुसंधान शामिल होंगे।

(ii) जाह्नवी भारत में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा की एक उत्साही समर्थक हैं - उन्होंने क्षुद्रग्रह खोज परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, आइसलैंड में ग्रहीय भूविज्ञान प्रशिक्षण में संलग्न हैं, और देश भर में ISRO और NIT परिसरों में व्याख्यान दिए हैं।

(iii) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु जैसे राजनीतिक नेताओं ने उनके चयन की प्रशंसा की है, जिन्होंने उन्हें युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती भूमिका का एक चमकदार उदाहरण बताया है।



23 जून 2025 को, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल (अगस्त 2023 - जुलाई 2024) के दौरान दिए गए 51 प्रभावशाली भाषणों का एक संग्रह "विंग्स टू ओवर होप्स - वॉल्यूम II" जारी किया। विमोचन समारोह राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

• भाषण संकलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र प्रमुख के रूप में दूसरे वर्ष के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। इसमें अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर दिए गए राष्ट्रीय विकास, संवैधानिक मूल्यों, समावेशी शासन और नागरिक-केंद्रित विकास पर उनके भाषणों पर प्रकाश डाला गया है।

• इस पुस्तक का संकलन राष्ट्रपति भवन द्वारा किया गया है तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन प्रभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का हिंदी संस्करण भी "आशाओं की उड़ान - खंड 2" शीर्षक के तहत लॉन्च किया गया है, जिससे व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई है।

• पुस्तक विमोचन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और प्रकाशन विभाग और MIB के वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Key Points:-

(i) यह संकलन नीति निर्माताओं, सिविल सेवा उम्मीदवारों,

BOOKS & AUTHORS

1. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 51 भाषणों के संकलन 'विंग्स टू ओवर होप्स - वॉल्यूम II' का विमोचन किया।

शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान संसाधन और संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह सामाजिक न्याय, डिजिटल सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण, महिला-नेतृत्व वाले विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।

(ii) विंग्स टू आवर होप्स - वॉल्यूम II का ई-बुक संस्करण अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, ताकि भारत भर के युवाओं और ज्ञान चाहने वालों के लिए डिजिटल पहुँच सुनिश्चित की जा सके। इसकी सामग्री भारत के 2047 के विकास लक्ष्यों और संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iii) पहला संस्करण, विंग्स टू आवर होप्स - वॉल्यूम I, जिसमें राष्ट्रपति के प्रथम वर्ष के भाषणों (जुलाई 2022 – जुलाई 2023) को शामिल किया गया है, जुलाई 2023 में जारी किया गया था। दोनों खंड मिलकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की नेतृत्व यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हैं और भारत के विकसित होते शासन और विकासात्मक आकांक्षाओं का जीवंत इतिहास प्रस्तुत करते हैं।

OBITUARY

1. अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप दोशी का लंदन में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



23 जून 2025 को भारत के पूर्व बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दिलीप रसिकलाल दोशी (77) का लंदन में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। 32 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले देर से उभरे दोशी ने 1979-83 के बीच 33 टेस्ट और 15 वनडे खेले और भारत के सबसे दिमागदार और शानदार स्पिनरों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की।

● दोशी ने मात्र 33 मैचों में 114 टेस्ट विकेट लिए, जिनमें छह बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है, तथा 15 एकदिवसीय मैचों में 22 विकेट लिए।

● उन्होंने चेन्नई (1979) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार टेस्ट पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने 6/103 और 2/64 विकेट लिए, और वे अपने पदार्पण टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले नौ भारतीयों में से एक बन गए।

Key Points:-

(i) प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक प्रमुख खिलाड़ी, दिलीप दोशी ने 238 मैचों में 898 विकेट हासिल किए, खास तौर पर बंगाल और सौराष्ट्र के लिए। उन्होंने नॉटिंगहमशायर और वारविकशायर के लिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया, जहाँ उन्होंने गैरी सोबर्स और इमरान खान जैसे दिग्गजों के साथ खेला।

(ii) 1981 में मेलबर्न में खेले गए टेस्ट मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर दोशी ने पैर की टूटी हुई उंगली के बावजूद गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए और भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके अटूट समर्पण की हर जगह प्रशंसा हुई।

(iii) क्रिकेट के “राजकुमार” के रूप में जाने जाने वाले दोशी, मैदान पर और मैदान के बाहर अपनी शान-शौकत के लिए जाने जाते थे। वे एक सज्जन व्यक्ति थे, खूब पढ़े-लिखे थे और मिक जैगर तथा अमर्त्य सेन जैसे साथियों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। सेवानिवृत्त होने के बाद भी, वे दुनिया भर के क्रिकेट जगत में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

Static GK

Tripura	मुख्यमंत्री: माणिक साहा	राज्यपाल: एन. इंद्रसेना रेड्डी
Ministry of Power (MoP)	केंद्रीय मंत्री: मनोहर लाल खट्टर	मुख्यालय: नई दिल्ली
Indian Railways (IR)	मंत्री: अश्विनी वैष्णव	मुख्यालय: नई दिल्ली
Adani New Industries Limited (ANIL)	MD & CEO : विनीत एस. जैन	मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात
Union Public Service Commission (UPSC)	अध्यक्ष: अजय कुमार (IAS)	मुख्यालय: नई दिल्ली
Indian Farmers Fertiliser Cooperative (IFFCO)	CEO : डॉ. उदय शंकर अवस्थी	मुख्यालय: नई दिल्ली
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Larsen & Toubro (L&T) Limited	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : शेखरीपुरम नारायणन (SN) सुब्रमण्यन	मुख्यालय: मुंबई
World Economic Forum	संस्थापक: क्लॉस श्वाब	मुख्यालय: कोलोग्नी, स्विटजरलैंड

S&P Global Ratings	अध्यक्ष : यान ले पैलेक	मुख्यालय : न्यूयॉर्क शहर
Finland	राजधानी: हेलसिंकी	प्रधान मंत्री: पेतेरी ओर्पो